



2026:AHC:29801

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1952 सन् 2026

मनोज कुमार और 11 अन्य
बनाम

.....याचिकाकर्ता(गण)

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: अर्चना सिंह, ब्रह्म नारायण सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. सिंह राठौर और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री आर.एस. उमराव को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि हालांकि रिट याचिकाकर्ताओं के कनिष्ठों और इसी तरह के पदधारियों को पीएसी से सशस्त्र पुलिस में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर विचार नहीं किया गया है।
3. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय प्रतिवादी संख्या 3, पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा पहली बार में किया जाना है।
4. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण रिट याचिकाकर्ताओं को रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और प्रतिवादी संख्या 3 के समक्ष आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक व्यापक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देने का निर्देश देने के लिए किया गया है, जो उक्त प्रस्ताव पर दो महीने की अवधि के भीतर रिट याचिकाकर्ताओं के दावे पर कानून के अनुसार आदेश की प्रमाणित प्रति के पेश करने की तारीख से सख्ती से विचार करने के लिए आगे बढ़ेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"